फेडरेशन ऑफ क्लास-1 ऑफीसर्स एसोसियेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया
ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन

संयुक्त अपील

मध्य क्षेत्र के सभी अधिकारियों, विकास अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम

दिनांक 5 मार्च 2020

विषय : शेयर बाजार में एलआईसी की सूचीबद्धता

प्रिय साथियों ,

इस विषय पर फेडरेशन ऑफ क्लास-1 आफीसर्स एसोसियेशन, एनएफआईएफडब्ल्यूआई एवं एआईआईईए द्वारा एक संयुक्त परिपत्र जारी किया गया है जिसे यहां पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है। विषय वस्तु स्वत: स्पष्ट है।

अभिवादन सहित

आपके साथी

के पी गुप्ता	**सौमित्र धर**	**डी आर महापात्र**
क्षेत्रीय महासचिव	क्षेत्रीय महासचिव	महासचिव
फेडरेशन ऑफ एलआईसी क्लास 1 ऑफिसर्स एसोसिएशन (मध्य क्षेत्र)	***नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया (मध्य क्षेत्र)***	***सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन***

प्रति,

समस्त एलआईसी कर्मचारियों को

प्रिय साथियों ,

एलआईसी की सूचीबद्धता एवं पॉलिसीधारकों को आत्मविश्वास प्रदान किये जाने की आवश्यकता ।

फेडरेशन ऑफ क्लास-1 ऑफीसर्स एसोसियेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया तथा ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन के नेतृत्व ने 23 फरवरी 2020 को तिरुअनंतपुरम में मुलाकात की तथा एलआईसी को सूचीबद्ध किये जाने के मुद्दे पर अत्यंत विस्तार से चर्चा की। संयुक्त मोर्चा की बैठक ने आईपीओ (इनीशियल पब्लिक ऑफर) के माध्यम से एलआईसी में अपनी भागीदारी को शेयर मार्केट में सूचीबद्ध किये जाने के सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ 4 फरवरी 2020 को 1 घंटे की बहिर्गमन हड़ताल के आव्हान को देशभर में शानदार रूप से सफल बनाने हेतुसमस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाइयां दीं। बैठक ने संतोषप्रद रूप से नोट किया कि हमारे अभिकर्ता मित्रों ने बड़ी संख्या में भागीदारी कर इस औद्योगिक कार्यवाही के साथ एकजुटता अभिव्यक्त की।

इस तात्कालिक हड़ताली कार्यवाही की सफलता इसके खिलाफ गहरे आक्रोश एवं एलआईसी को सूचीबद्ध किये जाने के सरकारी प्रयासों को पीछे धकेलने हेतु प्रतिरोध निर्मित किये जाने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। बैठक का यह मत था कि एलआईसी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किये जाने का निश्चित रूप से कोई कारण नहीं है। स्पष्ट रूप से यह उस सरकार द्वारा किया जा रहा बेताबीपूर्ण उपाय है, जो सरकार अर्थव्यवस्था में खराब प्रबंधन के चलते संसाधनों के गंभीर संकट का सामना कर रही है।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों ने पिछड़ी कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिकीकरण का आधार निर्मित किये जाने की नींव डाली थी। एलआईसी ने छोटी बचतों को एकत्रित कर दीर्घकालीन निवेश हेतु उसे पूंजी में परिवर्तित कर आधारभूत ढांचे हेतु उपलब्ध कराने के माध्यम से इस प्रक्रिया को स्थापित किया था। एलआईसी ने भारत के औद्योगिकीकरण में सहायता प्रदान कर गौरवपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया तथा उसी वक्त पॉलिसी राशि की पूर्ण सुरक्षा करते हुए पॉलिसीधारकों को आकर्षक वापसी सुनिश्चित की। इस प्रक्रिया में एलआईसी देश की प्रमुख एवं प्रभावी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान बनकर उभरी। उस देश में जो आज भी कम आय से जूझ रहा है, जहां भूख एवं गरीबी विचलित करने वाली सच्चाइयां हैं, एलआईसी को यह श्रेय जाता है कि उसने पर्याप्त संख्या में भारतीयों को बीमित किया एवं उन्हें अत्यंक आवश्यक सुरक्षा प्रदान की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एलआईसी देश का बहुत प्रशंसित संस्थान एवं अत्यधिक कीमती ब्राण्ड बन गया है।

....निरंतर

बैठक का यह मत था कि व्याकुल या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह पहला अवसर नहीं है जब इस प्रकार का हमला किया गया है। पी.व्ही. नरसिंहराव सरकार द्वारा नियुक्त मल्होत्रा कमेटी ने एलआईसी हेतु पूंजी जुटाने के लिए 50 प्रतिशत को बाजार में विनिवेशित किये जाने की अनुशंसा की थी। इसी क्रम में, बाजपेयी सरकार के दौरान प्रबंधकीय सलाहकार डेलॉयट ने एलआईसी की कार्यप्रणाली में बेहतरी हेतु इसकी पुनर्संरचना किये जाने का सुझाव दिया था। डेलॉयट की यह अनुशंसा थी कि पूंजी को बढ़ाकर एलआईसी का निगमीकरण किया जाये तथा इसके पश्चात पर्याप्त हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगाया जाये जिसे वे निगम के वास्तविक मूल्य को अनलॉक किया जाना कहते थे। उक्त दोनों सरकारों के लिए इन अनुशंसाओं को क्रियान्वित कर पाना असंभव रहा क्योंकि जनता एलआईसी के साथ थी। एलआईसी के शेयरों को बेचे जाने का एक बार पुन: प्रयास उस वक्त किया गया था, जब 2016 में वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली एलआईसी के स्वर्ण जयंती समारोह में सम्मिलित होने आये थे। एलआईसी की सफलता को स्वीकार करते हुए उन्होंने रेखांकित किया था कि यदि इसे स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध कर दिया जाये तो यह भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन जायेगी, इसलिए वर्तमान वित्तमंत्री की यह घोषणा आश्चर्यजनक नहीं है। भारतीय जनता को ज्ञात है कि सुरक्षा में एलआईसी सर्वश्रेष्ठ है, वे लोग इसके कार्य से प्रभावित हैं, वे लोग इसके राष्ट्रीय महत्व तथा राष्ट्रीय विकास में इसके विशाल योगदान से परिचित हैं। एलआईसी के पक्ष में जनता की ये मजबूत भावनाएं उसके कर्मचारियों के गौरवपूर्ण प्रतिरोध के साथ युग्मित होकर सरकार को अपनी योजना में सफल नहीं होने देती। इस शानदार संघर्ष ने एक चौथाई सदी में सरकार की नीतियों को रोके रखा है। दुनिया में मेहनतकशों के प्रतिरोधी आंदोलनों के इतिहास में इस प्रकार का दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। निजीकरण के पक्षकारों का तर्क है क्योंकि सरकार अपने संस्थानों के बेल आऊट हेतु एलआईसी का उपयोग करती रहती है इस स्थिति में प्रशासन में पारदर्शिता से ही पॉलिसीधारकों के हित सुरक्षित हो सकते हैं और ऐसा तभी संभव है जब सरकार इस पर अपने स्वामित्व में कमी करे। ये सारे तर्क सत्य नहीं है। यदि आज एलआईसी सर्वाधिक मूल्यवान संस्थान है तो यह इस कारण से है क्योंकि इसके प्रशासन में पारदर्शिता है तथा यह कुशल बोर्ड के द्वारा प्रबंधित संस्थान है।

ये पैरोकार इस बात से अनभिज्ञ नहीं हो सकते हैं कि जीवन बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता निजी क्षेत्र के कुप्रबंधन एवं धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहारों के चलते निर्मित हुई थी। हम इस पर सहमत हैं कि निवेश निर्णयों तथा कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तों के मुद्दों पर अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता इसकी शक्ति में और ज्यादा बढ़ोत्तरी करेगी। यह तर्क कि निजी क्षेत्र ज्यादा अच्छे से संचालित होते हैं, पूर्णत: गलत है। वित्तीय क्षेत्र में ऐसे असंख्यों उदाहरण हैं जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने विफल निजी बैंकों का अधिग्रहण कर प्रशंसनीय कार्य किया है। एलआईसी द्वारा आईआरडीए नियंत्रक के दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेश किया जाता है। उनके द्वारा एनपीए में बढ़ोत्तरी को चिन्हांकित किया गया है। एलआईसी का सर्वाधिक निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में है जो पूर्णत: सुरक्षित हैं। इक्विटी में निवेशों में मुनाफा अर्जित करने का पिछला रिकार्ड बहुत अच्छा है। इसके कार्पोरेट ऋण सशक्त क्रेडिट रेटिंग्स के आधार पर निवेशित किये जाते हैं। यह सही है कि अन्य व्यवसायिक संस्थानों की भांति एलआईसी के निवेश में भी कुछ जोखिम होते हैं, जो खराब लोन में परिवर्तित हो गये हैं। परंतु एनपीए बढ़ने का भय पैदा करना पूर्णत: अनुचित है। इसका डर दिखाकर ये पैरोकार एलआईसी कर्मचारियों के खून-पसीने से निर्मित विशाल संपत्ति को इस देश के धनिकों के हाथों में स्थानांतरित करने का अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं।

संयुक्त मोर्चा की बैठक में यह तय किया गया कि अब यह हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है कि पॉलिसीधारकों एवं आम जनता को जानकारी दें कि उनके हित पूर्णत: सुरक्षित हैं। एलआईसी अत्यधिक शक्तिशाली वित्तीय संस्थान है। इस वित्तीय संस्थान की शक्ति ट्रेड यूनियन आंदोलन की सतर्कता के साथ मिलकर पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। यह त्वरित कार्यभार है कि जिसे ट्रेड यूनियन आंदोलन को समझने की आवश्यकता है ताकि एलआईसी के नव व्यवसाय की गति को बनाये रखा जा सके। कर्मचारियों को यह समझना होगा कि विनिवेशीकरण की प्रक्रिया आईपीओ के रूप में एक छोटे हिस्से की बिक्री कर समाप्त नहीं होने वाली है। विद्यमान नियमो के अनुसार किसी भी सूचीकृत कंपनी के न्यूनतम 35 प्रतिशत शेयर बाजार में चलायमान होते हैं। इसलिए एलआईसी की हिस्सेदारी को शेयर मार्केट में बेचने हेतु हमले जारी रहेंगे। अन्य संस्थानों का अनुभव बताता है कि विनिवेशीकरण का अंतिम लक्ष्य निजीकरण है। इसलिए एलआईसी में विनिवेशीकरण का कोई आधार नहीं है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बाजार में अपने शेयर बिक्री करते हैं तो अपने संचालन हेतु पूंजी एकत्रित करने एवं नियंत्रणकारी प्रावधानों के लिए ऐसा किया जा रहा है। एलआईसी के मामले में यह संस्था सरकारी वित्त को पोषित करती है। सरकार के दैनंदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम इस 'मुकुट के हीरे' को बेचने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। एलआईसी के ट्रेड यूनियन आंदोलन को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक निरंतर चलनेवाले अभियानात्मक कार्यक्रम को लेना होगा। एलआईसी राष्ट्रीय परिसंपत्ति है तथा यह जनता की सबसे बहुमूल्य संपदा के रूप में बनी रहना चाहिए।

बैठक में यह तय किया गया कि हमारी संबद्ध इकाइयों को सूचीबद्ध किये जाने के विभिन्न पहलुओं पर सदस्यता को शिक्षित करना चाहिए तथा पॉलिसीधारकों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। मीटिंग का यह भी मत था कि एलआईसी को सूचीबद्ध किये जाने के मुद्दे पर समान समझ वाले अन्य संगठनों के पास पहुंचकर एकता को विस्तारित किया जाये।

क्रान्तिकारी अभिवादन सहित...

आपके साथी

-सही-	-सही-	-सही-
(एस. राजकुमार)	**(विवेक सिंह)**	**(श्रीकांत मिश्रा)**
महासचिव	महासचिव	महासचिव
फेडरेशन ऑफ एलआईसी क्लास-1	नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस	ऑल इंडिया इंश्योरेंस
आफीसर्स एसोसियेशन	फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया	एम्पलाईज एसोसियेशन